Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

24 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. भारत ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 6 करोड़ जांच के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की।

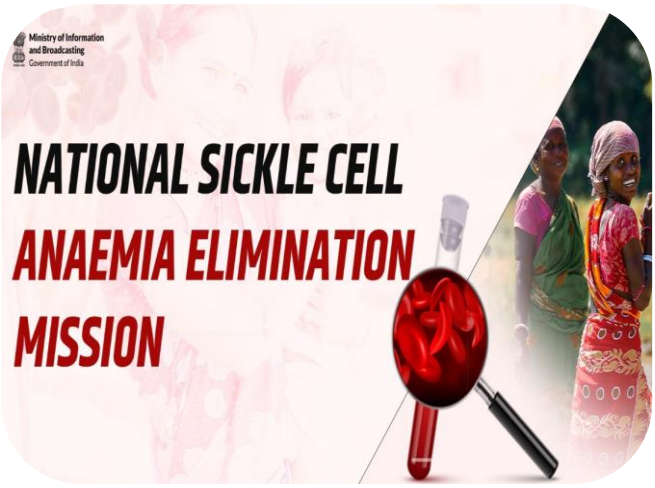

22 जुलाई 2025 को, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने घोषणा की कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सिकल सेल रोग (SCD) के लिए 6 करोड़ व्यक्तियों की जांच की गई है, जिससे देश 2026 से पहले 7 करोड़ स्क्रीनिंग लक्ष्य के करीब पहुंच गया है।

- **जांच किए गए 6 करोड़ लोगों में से लगभग 2.15 लाख व्यक्तियों में सिकल सेल रोग का निदान किया गया, तथा 16.7 लाख व्यक्तियों की पहचान सिकल सेल लक्षण के वाहक के रूप में की गई - जो जनसंख्या में रोग के बोझ और आनुवंशिक प्रवृत्ति दोनों को उजागर करता है।**

- **मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने अपने स्क्रीनिंग लक्ष्यों को पार कर लिया है। कुल मिलाकर, स्क्रीनिंग किए गए व्यक्तियों को 2.6 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें मिशन के तहत देखभाल की निरंतरता में एकीकृत किया गया है।**

- **स्क्रीनिंग मान्य पॉइंट-ऑफ-केयर टेस्टिंग (POCT) किट का उपयोग करके की जाती है, जिससे तेज़, विश्वसनीय और पुष्टिकारक परिणाम सुनिश्चित होते हैं। मिशन में वास्तविक समय पर नज़र रखने और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डेटा डैशबोर्ड और एक राष्ट्रीय SCD रोग पोर्टल भी शामिल है।**

Key Points:-

(i) इस मिशन का उद्घाटन 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में किया था, जिसका लक्ष्य उच्च प्रसार वाले और आदिवासी जिलों में 0-40 वर्ष की आयु के लोगों की सार्वभौमिक जाँच करना है। इसका लक्ष्य भारत के अमृत काल दृष्टिकोण के अनुरूप, 2047 तक SCD को एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है।

(ii) आगे बढ़ते हुए, मिशन विशेष रूप से कमज़ोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में, अवशिष्ट स्क्रीनिंग प्रयासों को तेज़ करने पर ज़ोर देता है। इसका उद्देश्य निदान-संबंधी परामर्श और देखभाल सेवाओं को मज़बूत करना, उपचार की सुलभता सुनिश्चित करना और चिन्हित आबादी में निवारक रणनीतियों के माध्यम से रुग्णता को कम करना है।

INTERNATIONAL

1. विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि 2030 तक भारतीय शहर 70% नौकरियां पैदा करेंगे, लेकिन बाढ़ से प्रतिवर्ष 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा।

विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट, जो केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ सह-लिखित है, में कहा गया है कि 2030 तक भारतीय शहर 70% नई नौकरियां पैदा करेंगे, लेकिन अनुकूलन उपायों के बिना, शहरी बाढ़ से प्रति वर्ष 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, जिससे शहरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा जलवायु जोखिम पैदा हो सकता है।

- **अनुमान है कि भारत की शहरी आबादी 2020 में 480 मिलियन से बढ़कर 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 951 मिलियन हो जाएगी, तथा इस वृद्धि को स्थायी रूप से संभालने के लिए आवास, परिवहन, जल और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।**

- **विश्व बैंक का अनुमान है कि 2030 तक 70% नए रोजगार सृजन शहरी क्षेत्रों में होंगे, जो शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में रेखांकित करता है; हालांकि, कंक्रीट सतहों का अनियोजित विस्तार वर्षाकालीन बाढ़ के खतरों को बढ़ाता है।**

- **रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि शहरों ने पूर्व चेतावनी प्रणाली, शहरी हरियाली और सुदृढ़ जल निकासी अवसंरचना जैसी अनुकूलन रणनीतियों में निवेश नहीं किया, तो बाढ़ से संबंधित वार्षिक क्षति 2030 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है, जो 2070 तक बढ़कर 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी।**

Key Points:-

(i) लचीलापन बनाने के लिए, भारतीय शहरों को 2050 तक अनुमानतः 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, जो मध्यम शहरीकरण के तहत 2070 तक बढ़कर 10.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा; इसके लिए निजी क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ाने के साथ-साथ केंद्रीय, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी।

(ii) रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ULBs को अधिक स्वायत्तता मिलने से कुछ शहरों को संसाधन जुटाने, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने और शासन में सुधार करने में मदद मिली है, जिससे यह संकेत मिलता है कि स्थानीय सशक्तिकरण बढ़ने से जलवायु संबंधी झटकों के प्रति संवेदनशीलता कम हो सकती है।

(iii) 2030 तक, तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और बढ़ते जलवायु तनाव के साथ, भारतीय शहरों के सामने दोहरी चुनौती होगी: रोज़गार-केंद्रित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और साथ ही मज़बूत बाढ़ अनुकूलन प्रणालियाँ लागू करना। इसमें जीवन, आजीविका और भविष्य के विकास की सुरक्षा के लिए ठंडी छतें, पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ और मैंग्रोव पुनर्स्थापन शामिल हैं।

2. भारत 24 जुलाई से चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना पुनः शुरू करेगा, जिससे पांच साल का निलंबन समाप्त हो जाएगा।

एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विकास में, भारत 24 जुलाई 2025 से चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू करेगा, जिससे 2020 के गलवान सीमा संघर्ष और कोविड-19 महामारी के बाद लगाए गए लगभग पांच साल के निलंबन को समाप्त किया जा सकेगा।

• वीज़ा पर रोक मार्च 2020 की शुरुआत में शुरू हुई थी, जब पूर्वी लद्दाख में एक घातक सैन्य टकराव के बाद बढ़ते तनाव के बीच पर्यटक वीज़ा निलंबित कर दिए गए थे। इसके बाद के प्रतिबंधों में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध, निवेश पर कड़ी निगरानी और सीधी उड़ानों में कटौती शामिल थी। हालाँकि व्यावसायिक और छात्र वीज़ा धीरे-धीरे बहाल कर दिए गए थे—चीन ने 2022 में इन्हें फिर से जारी करना शुरू कर दिया था—लेकिन इस हफ़्ते की घोषणा तक पर्यटन पर प्रतिबंध लगा रहा।

• यह निर्णय 2024-25 में संबंधों में सुधार लाने के उद्देश्य से राजनयिक वार्ताओं की एक श्रृंखला के बाद लिया गया है। उच्च-स्तरीय अधिकारियों ने सीधी उड़ानों की बहाली, कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा और लोगों के बीच सहज आदान-प्रदान के लिए वीज़ा उदारीकरण पर बातचीत की।

Key Points:-

(i) 24 जुलाई से, चीनी नागरिक बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझोउ स्थित भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्रों (IVACs) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज़ जमा करने होंगे; यदि बीजिंग केंद्र से पासपोर्ट वापस लिए जाते हैं, तो एक औपचारिक वापसी पत्र की आवश्यकता होगी।

(ii) चीन ने भारत के इस कदम का स्वागत किया और उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह द्विपक्षीय संचार और लोगों के बीच आदान-प्रदान को मज़बूत करने के लिए तैयार है। भारत ने ज़ोर देकर कहा कि पूर्ण सामान्यीकरण के लिए सैन्य गतिरोध को दूर करना, सैनिकों की वापसी और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों से बचना आवश्यक होगा।

(iii) इस वापसी से पर्यटन को पुनर्जीवित करने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंधों को सुधारने की उम्मीद है। उम्मीद है कि यह कदम भविष्य में उच्च-स्तरीय बैठकों के दौरान सहयोग को बढ़ावा देगा, जिसमें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित चीन यात्रा भी शामिल है।

3. ब्रिटेन और भारत ने कीर स्टारमर और नरेंद्र मोदी के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया, प्रमुख निर्यातों पर शुल्क में कटौती की।

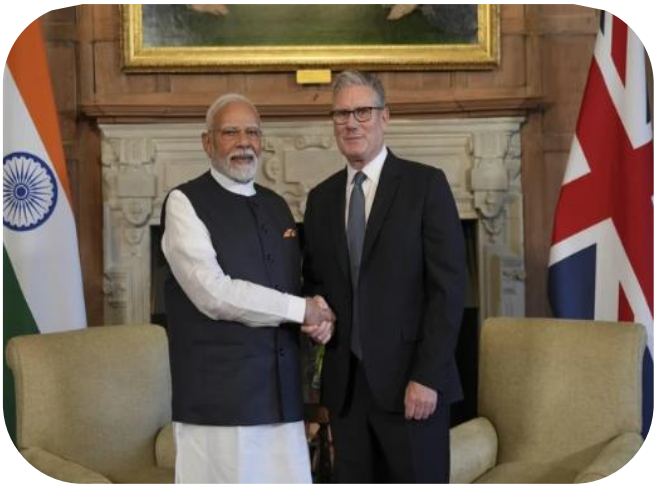

24 जुलाई 2025 को, यूनाइटेड किंगडम और भारत की सरकारों ने तीन साल की बातचीत के बाद, एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को आर्थिक सहयोग के एक नए युग के रूप में सराहा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और एक-दूसरे के प्रमुख निर्यात बाजारों तक पहुँच बढ़ेगी।

• यह समझौता ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन द्वारा हस्ताक्षरित सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता और भारत द्वारा अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है। 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में शुरू हुई और दोनों देशों में नेतृत्व परिवर्तन के बाद संपन्न हुई भारत-ब्रिटेन वार्ता के तहत, इस मुक्त व्यापार समझौते का

उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना और पारस्परिक आर्थिक लाभ प्रदान करना है।

• इस समझौते के तहत, भारत ब्रिटेन को किए जाने वाले अपने 99% निर्यातों पर आयात शुल्क समाप्त कर देगा, जिससे कपड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, और समुद्री उत्पादों जैसे भारतीय क्षेत्रों को लाभ होगा। इस बीच, भारत 90% ब्रिटिश निर्यातों पर शुल्क कम करेगा, और एक दशक के भीतर 85% पूरी तरह से शुल्क-मुक्त हो जाएँगे। व्हिस्की और जिन जैसी ब्रिटिश स्पिरिट पर शुल्क तुरंत 150% से घटाकर 75% कर दिया जाएगा, और अंततः 40% तक कम हो जाएगा; एक कोटा योजना के तहत ब्रिटिश ऑटोमोबाइल पर शुल्क 100% से घटकर केवल 10% रह जाएगा।

• - इस समझौते से ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष 4.8 बिलियन पाउंड की वृद्धि, ब्रिटिश वेतन में 2.2 बिलियन पाउंड की वृद्धि, तथा 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 बिलियन पाउंड का विस्तार होने का अनुमान है। भारत को इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों, कृषि एवं खाद्य उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स तथा IT सेवाओं के लिए शून्य-शुल्क पहुंच से महत्वपूर्ण निर्यात वृद्धि प्राप्त होने की उम्मीद है।

Key Points:-

(i) अभिनव रियायतों में एक दोहरा अंशदान समझौता शामिल है, जिसके तहत ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय पेशेवरों और भारत में कार्यरत ब्रिटेन के पेशेवरों को तीन वर्षों तक मेजबान देश के सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलती है। यह समझौता रसोइयों, योग प्रशिक्षकों, संगीतकारों और आईटी प्रतिभाओं के लिए अस्थायी वीज़ा मार्ग भी खोलता है, जिससे लोगों के बीच संपर्क और सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ता है।

(ii) दोनों देशों के नेताओं ने व्यापक रणनीतिक लाभों पर ज़ोर दिया: मोदी ने इस समझौते को "साझा समृद्धि का खाका" बताया, और स्टार्मर ने इसे ब्रेक्सिट के बाद से आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बताया, और व्यापार को गति देने, रोज़गार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देने का वादा किया। भारतीय डेयरी और चावल क्षेत्र जहाँ सुरक्षित बने रहेंगे, वहीं संवेदनशील कृषि वस्तुओं, सेवाओं और मूल व्यापार नियमों पर आगे की बातचीत जारी रहेगी।

(iii) यह मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बाज़ारों के साथ भारत के भावी व्यापार समझौतों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करेगा। इसके रणनीतिक प्रभाव सार्वजनिक खरीद तक पहुँच, निवेश सुगमता, डिजिटल व्यापार और रक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा ऊर्जा नवाचार में सहकारी ढाँचों तक फैले हुए हैं।

4. चीन ने यारलुंग त्सांगपो नदी (ब्रह्मपुत्र) पर दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध का निर्माण शुरू किया।

19 जुलाई 2025 को, चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने अरुणाचल प्रदेश के विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र के पास, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के न्यिंगची में एक अभूतपूर्व जलविद्युत परियोजना—यारलुंग ज़ंग्बो (त्सांगपो) जलविद्युत परियोजना—के निर्माण का उद्घाटन किया। यह विशाल परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा बाँध बनने वाली है और चीन के नवीकरणीय ऊर्जा अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी।

• चीन इस परियोजना में लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन (करीब 170 अरब अमेरिकी डॉलर) का निवेश कर रहा है, जो 50 किलोमीटर लंबी खड़ी घाटी में पाँच जलप्रपात जलविद्युत स्टेशनों को फैलाएगी—जहाँ यारलुंग त्सांगपो लगभग 2,000 मीटर नीचे गिरती है। 2030 के दशक की शुरुआत में चालू होने पर, यह परियोजना सालाना लगभग 300 अरब किलोवाट घंटा बिजली पैदा करेगी, जो थ्री गॉर्जेस बांध के उत्पादन को तीन गुना कर देगी।

• भारत और बांग्लादेश, दोनों ही निचले इलाकों के देशों ने चिंता व्यक्त की है। लाखों लोग पीने, सिंचाई और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी पर निर्भर हैं, इसलिए दिल्ली ने मौसमी प्रवाह, तलछट परिवहन और बाढ़ के पैटर्न में संभावित व्यवधानों के बारे में बार-बार चिंता जताई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि संघर्षों के दौरान निचले इलाकों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध का रणनीतिक रूप से उपयोग किया जा सकता है।

• पर्यावरणीय और भूकंपीय जोखिम इस विवाद को और बढ़ा रहे हैं। यह घाटी पृथ्वी की सबसे गहरी और सबसे जैव विविधता वाली घाटियों में से एक है, जो एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। स्वदेशी तिब्बती समुदायों के पुनर्वास और आवास के नुकसान के कारण पहले ही स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन और कठोर सरकारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आलोचक नाज़ुक पारिस्थितिक तंत्र पर अपरिवर्तनीय प्रभाव की चेतावनी दे रहे हैं।

Key Points:-

(i) चीन ने इस परियोजना का बचाव करते हुए इसे न्यूनतम भंडारण क्षमता वाली "नदी के बहाव" वाली परियोजना बताया है और दावा किया है कि इसका कठोर पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया है। अधिकारियों का दावा है कि इससे निचले इलाकों के जल स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह परियोजना आपदा निवारण, जलवायु लक्ष्यों और स्थानीय आर्थिक विकास का समर्थन करती है।

(ii) इस बीच, भारत अपनी जलविद्युत प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन कर रहा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना की योजना भी शामिल है, ताकि उसके निचले जल अधिकारों की रक्षा की जा सके और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

BANKING & FINANCE

1. SEBI ने ब्रोकरों के लिए केंद्रीकृत अनुपालन प्लेटफॉर्म 'सामूहिक प्रतिवेदन मंच' लॉन्च किया, जो 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा।

बाजार सहभागियों के लिए नियामक रिपोर्टिंग को सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के साथ मिलकर 'सामूहिक प्रतिवेदन मंच' नामक एक एकीकृत अनुपालन रिपोर्टिंग प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। यह पहल 1 अगस्त, 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य कई एक्सचेंजों में पंजीकृत स्टॉकब्रोकरों के लिए अतिरेक और अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना है।

• सामूहिक प्रतिवेदन मंच को दलालों के लिए अपने नियामक दायित्वों को पूरा करने हेतु एक एकल, पारदर्शी और लागत-कुशल तंत्र प्रदान करके अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए

डिज़ाइन किया गया है। अब तक, दलालों को प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को व्यक्तिगत रूप से बार-बार अनुपालन डेटा प्रस्तुत करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप दोहराए गए प्रयास और अक्षमता होती थी।

• यह प्लेटफ़ॉर्म आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त, 2025 को चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। पहले चरण में, एकीकृत इंटरफ़ेस में 40 प्रकार की अनुपालन रिपोर्ट शामिल की जाएँगी। ये रिपोर्ट वर्तमान में ब्रोकरों द्वारा अलग-अलग स्टॉक एक्सचेंजों को अलग-अलग जमा की जाती हैं, जिन्हें अब एकीकृत करके इस केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से जमा किया जाएगा।

• इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, कई स्टॉक एक्सचेंजों में काम करने वाले ब्रोकर अब एक ही इंटरफ़ेस के ज़रिए अपना अनुपालन डेटा एक बार में अपलोड कर पाएँगे, जिससे उन्हें कई बार डेटा जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे प्रशासनिक बोझ काफ़ी कम होगा, एकरूपता सुनिश्चित होगी और अनुपालन की लागत कम होगी।

Key Points:-

(i) बाद के चरणों में, अतिरिक्त अनुपालन दस्तावेज़ों को मानकीकृत किया जाएगा और उसी पोर्टल में शामिल किया जाएगा। इस पूर्ण एकीकरण से अंततः भारत के सभी ब्रोकर लाभान्वित होंगे, जिनमें मध्यस्थ और निवेशक-सेवा स्तर पर काम करने वाले ब्रोकर भी शामिल हैं, जिससे SEBI के व्यापक सुधार एजेंडे को बल मिलेगा।

(ii) SEBI के आंतरिक अनुमानों के अनुसार, एक से अधिक एक्सचेंजों की सदस्यता रखने वाले लगभग 990 स्टॉकब्रोकरों को इस अनुपालन प्लेटफ़ॉर्म से तुरंत लाभ मिलने की उम्मीद है। यह पहल भारतीय प्रतिभूति बाज़ार में व्यापार को आसान बनाने, विनियमन को सरल बनाने और काम के दोहराव को कम करने के सेबी के रणनीतिक प्रयासों के अनुरूप है।

(iii) यह कदम SEBI के व्यापक डिजिटल परिवर्तन दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसका उद्देश्य एक निर्बाध निवेशक और मध्यस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन 1988 में एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था और 12 अप्रैल, 1992 को संसद के एक अधिनियम के तहत यह एक सांविधिक निकाय बन गया।

2. RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक वित्त वर्ष 2025 में 4.3% बढ़कर 67 पर पहुंच गया।

जुलाई 2025 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बताया कि उसका समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-सूचकांक) वित्त वर्ष 24-25 में 4.3% बढ़कर 67 हो गया - जो मार्च 2024 में 64.2 था - जिसमें गहन सेवा उपयोग और साक्षरता प्रयासों द्वारा संचालित पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता उप-सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

• FI-सूचकांक, जो पहुँच (35%), उपयोग (45%) और गुणवत्ता (20%) का एक संयोजन है, बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक सेवाओं और पेंशन में समावेशन को मापता है। प्रत्येक उप-सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़ी हुई सेवा पहुँच, बेहतर उपयोग आवृत्ति और बेहतर उपभोक्ता अनुभव का संकेत देती है।

• RBI ने इस बात पर प्रकाश डाला कि FI-इंडेक्स में वृद्धि के प्राथमिक चालक उपयोग और गुणवत्ता आयाम थे - जो वित्तीय उत्पादों के अधिक लगातार उपयोग और बेहतर सेवा गुणवत्ता को दर्शाते हैं, जो अधिक वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण पहल द्वारा समर्थित हैं।

• सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से तैयार किया गया, एफआई-इंडेक्स 2021 में लॉन्च किया गया था। यह समावेशन को समग्र रूप से दर्शाने के लिए बिना किसी आधार वर्ष के 97 संकेतकों का उपयोग करता है। वित्त वर्ष 17 में 43.4 के आधार स्तर से, यह सूचकांक वित्त वर्ष 21 में बढ़कर 53.9, फिर वित्त वर्ष 24 में 64.2 और अब वित्त वर्ष 25 में 67 हो गया है।

Key Points:-

(i) वित्त वर्ष 24-25 में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 34.8% की वृद्धि देखी गई, जिसमें वैश्विक रीयल-टाइम भुगतानों में UPI का योगदान 48.5% रहा। इस डिजिटल गति ने, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, उपयोग में वृद्धि और वित्तीय पहुँच को बढ़ावा दिया।

(ii) यह वृद्धि वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFI 2019-24) और वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFE 2020-25) के तहत समन्वित प्रयासों को दर्शाती है, जिसमें वित्तीय साक्षरता केंद्रों का विस्तार, राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी अभियान और "जूनियर मनी" जैसे शुभंकर का उपयोग करने वाले अभियान शामिल हैं।

(iii) RBI ने अंतिम छोर तक पहुंच, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कमजोर समूहों के लिए अनुकूलित उत्पादों और बेहतर शिकायत निवारण के माध्यम से और अधिक प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया - जिससे अधिक समावेशी और सशक्त वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में काम किया जा सके।

3. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एनआरआई और नाविकों के लिए एफसीएनआर (बी) जमा और एक्सप्लोरर बचत खाता शुरू किया।

22 जुलाई 2025 को, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दो नए ऑफर पेश किए—विदेशी मुद्रा अनिवासी FCNR (B) जमा और इक्विटास एक्सप्लोरर बचत खाता। ये विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों (NRIs) और नाविकों को भारत के वैश्विक कार्यबल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लचीले, सुरक्षित और डिजिटल बैंकिंग समाधानों से सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

• भारत के प्रमुख लघु वित्त बैंकों (SFBs) में से एक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सीमा-पार मुद्रा जोखिम को कम करने हेतु FCNR (B) जमा योजना तैयार की है। अमेरिकी डॉलर में उपलब्ध, यह अनिवासी भारतीयों को अपनी विदेशी आय को सुरक्षित रखने में मदद करता है, रिटर्न पर कर-मुक्त ब्याज, मूलधन और ब्याज की पूर्ण प्रत्यावर्तनीयता, और नवीनीकरण में आसानी प्रदान करता है, जिससे यह एक मज़बूत धन प्रबंधन उपकरण बन जाता है।

• एक्सप्लोरर बचत खाता विशेष रूप से नाविकों, नाविकों और महासागरों के पार काम करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) के लिए है। अनिवासी बाह्य (NRE) और अनिवासी साधारण (NRO) दोनों रूपों में उपलब्ध, इस खाते में वीज़ा

प्लैटिनम डेबिट कार्ड, ₹1 करोड़ का हवाई दुर्घटना मृत्यु बीमा, ₹2 लाख का गृह सामग्री बीमा, रिश्तेदारों के लिए अधिदेश-धारक सुविधा और खाताधारकों के लिए रियायती लॉकर किराये जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

Key Points:-

(i) विदेशों में कार्यरत 2.85 लाख से ज़्यादा भारतीय नाविकों (जहाजरानी महानिदेशालय, 2023 के अनुसार) और दुनिया भर में 35.4 मिलियन से ज़्यादा अनिवासी भारतीयों के साथ, ये उत्पाद लॉन्च इक्विटास एसएफबी के भारत के प्रवासी समुदाय के लिए डिजिटल-प्रथम, ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को दर्शाते हैं। बैंक अपने बढ़ते वैश्विक ग्राहकों के लिए प्रत्यावर्तनीय, उच्च-ब्याज और सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

(ii) एक्सप्लोरर अकाउंट के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु आवेदकों को केवल ₹1 लाख का औसत मासिक बैलेंस (AMB) या ₹10 लाख का कुल संबंध मूल्य (TRV) बनाए रखना आवश्यक है। पासपोर्ट, वीज़ा या निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र (CDC) जैसे दस्तावेज़ों को दूरदराज के स्थानों में रहने वालों के लिए परेशानी को कम करने के लिए सुव्यवस्थित किया गया है।

(iii) इक्विटास SFB के वरिष्ठ अध्यक्ष और कंट्री हेड (शाखा बैंकिंग - देयताएं, उत्पाद और संपत्ति) मुरली वैद्यनाथन ने कहा कि ये पेशकशें बैंक के उस मिशन को दर्शाती हैं, जो सीमाहीन, लाभ-समृद्ध और प्रौद्योगिकी-आधारित समावेशी बैंकिंग समाधानों के साथ वंचित और विशिष्ट वर्गों को सशक्त बनाने के लिए है।

4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल NPA अनुपात वित्त वर्ष 2021 के 9.11% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 2.58% हो गया और परिसंपत्ति गुणवत्ता मजबूत हुई।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हालिया अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात वित्त वर्ष 2021 के 9.11% (₹6.16 लाख करोड़) से वित्त वर्ष 2025 में नाटकीय रूप से घटकर 2.58% (₹2.83 लाख करोड़) हो गया है। यह सुधार मज़बूत रिकवरी, नियामक सुधारों और संकटग्रस्त परिसंपत्तियों में निरंतर कमी को दर्शाता है।

- **हाल के वर्षों में सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (GNPAs) में भारी गिरावट निरंतर वसूली प्रयासों का परिणाम है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के कार्यान्वयन से NPAs का प्रभावी समाधान संभव हुआ और जानबूझकर चूक करने वालों को समाधान प्रक्रिया से बाहर रखा गया। दबाव की सख्त पहचान से खुदरा और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में नई चूक को सीमित करने में मदद मिली।**

- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025 में लगभग ₹58,000 करोड़ मूल्य के डूबे हुए ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया—यह बैलेंस शीट को दुरुस्त करने की रणनीति का एक हिस्सा है। यह आक्रामक बट्टे खाते में डालने की नीति पुराने NPA को कम करती है और परिसंपत्ति गुणवत्ता अनुपात में सुधार करती है, लेकिन यह ऋण वसूली और धोखाधड़ी की रोकथाम में जारी चुनौतियों का भी संकेत देती है।**

• RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर्याप्त पूंजीकृत हैं, जिनका कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) और पूंजी-जोखिम-भारित आस्तियों का अनुपात (CRAR) नियामक सीमाओं से काफी ऊपर है। हालाँकि, गंभीर दबाव की स्थिति में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल NPA मार्च 2025 तक 4.1% तक बढ़ सकता है, जो संभावित भेद्यता को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) विभिन्न ऋण श्रेणियों में GNPA अनुपात एक समान हो गए हैं; खुदरा ऋणों में तनाव का स्तर सबसे कम रहा, जबकि कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में एनपीए अधिक दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि खुदरा जीएनपीए लगभग 1.2% (सितंबर 2024) रहा, जबकि कृषि क्षेत्र में यह 6.2% रहा। यह प्रवृत्ति सतर्क ऋण और प्रभावी ऋण वितरण को दर्शाती है।

(ii) 2015 की शुरुआत में, भारत सरकार ने डूबते ऋणों से निपटने के लिए 4R ढाँचा—पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार—शुरू किया। RBI के तहत परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR) के बाद, NPA की व्यवस्थित पहचान और पुनर्पूंजीकरण उपायों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैलेंस शीट को काफ़ी मज़बूत किया। CRAR 11.45% (मार्च 2015) से बढ़कर 15.43% (सितंबर 2024) हो गया।

(iii) बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता रिकॉर्ड मुनाफ़े में तब्दील हुई—सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 24 में ₹1.41 लाख करोड़ का कुल शुद्ध लाभ दर्ज किया—जो अब तक के सबसे मज़बूत प्रदर्शनों में से एक है। बेहतर ADS (अग्रिम-से-जमा), बेहतर प्रावधान बफर, और अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का निरंतर क्रियान्वयन एक मज़बूत, समावेशी बैंकिंग क्षेत्र को दर्शाता है।

5. RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक में 9.99% हिस्सेदारी अधिग्रहण के माध्यम से वारबर्ग पिंकस निवेश को मंजूरी दी।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वैश्विक निजी इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकस की सहयोगी कंपनी करंट सी इन्वेस्टमेंट्स बी.वी. को IDFC फर्स्ट बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंज़ूरी दे दी है। बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई जानकारी के अनुसार, जुलाई 2025 के मध्य में इस मंज़ूरी की घोषणा की गई है। यह मंज़ूरी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा 3 जून 2025 को मंज़ूरी दिए जाने के बाद दी गई है।

• वारबर्ग पिंकस ₹60 प्रति शेयर की कीमत वाले 81.27 करोड़ अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान्य शेयर (CCPS) खरीदकर लगभग ₹4,876 करोड़ (लगभग 587 मिलियन अमेरिकी डॉलर) निवेश करने की योजना बना रहा है। एक बार परिवर्तित होने पर, ये शेयर बैंक में अधिकतम 9.99% हिस्सेदारी के बराबर होंगे।

Key Points:-

(i) यह पूंजी निवेश ₹7,500 करोड़ के एक बड़े धन उगाहने वाले अभियान का हिस्सा है, जिसमें अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) द्वारा अपनी प्लैटिनमइन्विक्टस शाखा के माध्यम से ₹2,624 करोड़ का निवेश भी शामिल है। रूपांतरण के बाद,

यह संयुक्त विदेशी निवेश IDFC फर्स्ट बैंक की चुकता शेयर पूंजी का लगभग 15% होगा, जिससे इसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात ~16.1% से बढ़कर ~18.9% और CET-1 अनुपात लगभग 16.5% हो जाएगा।

(ii) हालाँकि, कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं। बैंक के बोर्ड में वारबर्ग से संबद्ध एक नामिती की नियुक्ति का शेयरधारक प्रस्ताव हाल ही में विफल रहा, जिसे केवल 64.1% अनुमोदन प्राप्त हुआ, जो अनिवार्य 75% की सीमा से कम है। इसके बावजूद, प्रबंधन को नियामक अनुमोदनों और पूँजी नियोजन योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए इस मुद्दे को सुलझाने का भरोसा है।

6. फिनो पेमेंट्स बैंक ने UPI अपनाने को तेजी से बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल में "गति" बचत खाता लॉन्च किया।

24 जुलाई 2025 को, फिनो पेमेंट्स बैंक ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को लक्षित करते हुए, "गति" नाम से अपना शून्य-शेष डिजिटल बचत खाता शुरू किया। त्वरित ऑनबोर्डिंग और तत्काल UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) एक्टिवेशन के लिए डिज़ाइन की गई इस पहल का उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करना है।

• गति खाता—जिसका अर्थ कई भारतीय भाषाओं में गति होता है—पश्चिम बंगाल में 40,000 से ज़्यादा व्यापारी केंद्रों पर E-KYC प्रमाणीकरण के ज़रिए तुरंत खोला जा सकता है। यह मॉडल फिनो के व्यापारी-आधारित नेटवर्क का लाभ उठाकर ऑनबोर्डिंग को आसान बनाता है और उपयोगकर्ताओं को भौतिक (फिजिटल) बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग में संक्रमण में सहायता प्रदान करता है।

• डिजिटल रूप से रुचि रखने वाले लेकिन वंचित समूहों—जैसे युवा, महिलाएं, कल्याणकारी लाभार्थी और वरिष्ठ नागरिक—को ध्यान में रखकर बनाए गए इस GATI खाते के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है और इसमें ₹100 का एकमुश्त उद्घाटन शुल्क और ₹50 का त्रैमासिक रखरखाव शुल्क शामिल है, जिससे यह किफायती और सुलभ हो जाता है। FinoPay ऐप के माध्यम से UPI ID स्वतः जनरेट होती है, जिससे तत्काल लेनदेन की सुविधा मिलती है।

Key Points:-

(i) यह लॉन्च फिनो की व्यापक डिजिटल समावेशन रणनीति के अनुरूप है: वंचित उपयोगकर्ताओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सक्रिय भागीदार बनाना। यह कदम दूरदराज के इलाकों में मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए तुरंत, कम लागत वाली वित्तीय पहुँच प्रदान करके डिजिटल इंडिया मिशन का समर्थन करता है।

(ii) फिनो का लक्ष्य अर्ध-शहरी और ग्रामीण बंगाल में UPI अपनाने को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है, जहाँ स्मार्टफोन का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन डिजिटल बैंकिंग की पहुँच सीमित है। गति पहल उपयोगकर्ताओं को तत्काल P2P (पीयर-टू-पीयर) और पी2एम (पर्सन-टू-मर्चेंट) लेनदेन करने में सक्षम बनाती है, जिससे वित्तीय समावेशन और नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों में योगदान मिलता है।

7. फोनपे और SBI कार्ड ने डिजिटल खर्च को बढ़ावा देने के लिए दो सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए।

22 जुलाई, 2025 को, डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म फ़ोनपे ने SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (भारतीय स्टेट बैंक - SBI की एक सहायक कंपनी) के साथ मिलकर दो को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है 'फ़ोनपे SBI कार्ड पर्पल' और 'फ़ोनपे SBI कार्ड सेलेक्ट ब्लैक'। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य डिजिटल क्रेडिट पहुँच को बढ़ावा देना और औपचारिक वित्तीय माध्यमों के माध्यम से रोज़मर्रा के खर्च को प्रोत्साहित करना है।

- **ये दोनों नए लॉन्च किए गए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड वीज़ा और रुपे नेटवर्क पर काम करेंगे। वीज़ा कार्ड फ़ोनपे ऐप के ज़रिए टोकनाइज़ेशन के लिए सपोर्टेड हैं, जबकि रुपे वर्जन को सीधे UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस) से जोड़ा जा सकता है, जिससे सभी प्लेटफॉर्म पर निर्बाध डिजिटल लेनदेन संभव हो सकेगा।**

- **फ़ोनपे SBI कार्ड, किराने की खरीदारी, बिजली बिल भुगतान, बीमा प्रीमियम और फ़ोनपे एप्लिकेशन के माध्यम से किए जाने वाले अन्य सभी लेन-देन सहित दैनिक खर्चों की एक विस्तृत श्रृंखला पर पुरस्कार-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। ये कार्ड विविध ग्राहक वर्गों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।**

- **प्रीमियम वैरिएंट, फ़ोनपे SBI कार्ड सेलेक्ट ब्लैक, फ़ोनपे ऐप और पिनकोड पर किए गए खर्च पर 10% तक कैशबैक और अन्य मर्चेंट प्लेटफ़ॉर्म पर 5% कैशबैक प्रदान करता है। इसमें ₹1,500 मूल्य का वेलकम ई-गिफ्ट वाउचर और ₹5 लाख से अधिक के वार्षिक खर्च पर ₹5,000 मूल्य का माइलस्टोन वाउचर जैसे लाभ भी शामिल हैं।**

Key Points:-

(i) दूसरी ओर, फोनपे SBI कार्ड पर्पल, नियमित उपयोगकर्ताओं को लक्षित करते हुए, फोनपे और पिनकोड लेनदेन पर 3% और अन्य ऑनलाइन खरीद पर 2% पुरस्कार प्रदान करता है।

(ii) अतिरिक्त यात्रा और ई-उपहार वाउचर में ₹500 का स्वागत उपहार और प्रति वर्ष ₹3 लाख खर्च करने पर ₹3,000 का वार्षिक यात्रा वाउचर शामिल है।

(iii) आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है और फोनपे मोबाइल एप्लिकेशन में अंतर्निहित है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से आवेदन कर सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट देख सकते हैं, बिल ट्रैक कर सकते हैं और वाउचर रिडीम कर सकते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को ऐप के माध्यम से सीधे अपने बकाया का भुगतान करने या वाउचर रिडीम करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

SPORTS

1. जापान बैडमिंटन ओपन 2025 - शि यू क्यू ने पुरुष एकल और एन से-यंग ने महिला एकल का खिताब जीता।

टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में 15 से 20 जुलाई 2025 तक आयोजित, BWF (बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन) वर्ल्ड टूर सुपर 750 श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित जापान ओपन 2025, उल्लेखनीय जीत के साथ संपन्न हुआ। चीन के शी यू की ने पुरुष एकल का खिताब जीता, जबकि दक्षिण कोरिया की एन से-यंग ने महिला एकल का खिताब जीतकर अपना दबदबा बरकरार रखा।

• पुरुष एकल फाइनल में, शीर्ष वरीयता प्राप्त चीनी शटलर शि यू की ने फ्रांस के एलेक्स लेनियर को सीधे सेटों में 21-17, 21-15 के स्कोर से हराया। यह जीत मलेशिया ओपन और ऑल इंग्लैंड ओपन में जीत के बाद, 2025 सीज़न में शि का तीसरा BWF विश्व टूर खिताब है। उनकी जीत ने जापान ओपन में पुरुष एकल में चीन के दस साल के खिताबी सूखे को भी समाप्त कर दिया, जहाँ पिछली जीत लिन डैन ने 2015 में हासिल की थी।

• उनकी जीत ने न केवल उन्हें 11,000 बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग अंक दिलाए, बल्कि आगामी चाइना ओपन 2025 में दुनिया के शीर्ष दावेदारों में उनकी जगह भी पक्की कर दी।

• महिला एकल फ़ाइनल में, वर्तमान विश्व नंबर 1 और मौजूदा विश्व चैंपियन, एन से-यंग ने चीन की वांग झीयी को 21-12, 21-10 के प्रभावशाली स्कोर से हराया। यह मैच सिर्फ़ 38 मिनट तक चला, जिसमें एन की बेहतरीन कोर्ट कवरेज, शॉट चयन और मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन था। इस जीत ने 2025 में उनका छठा BWF वर्ल्ड टूर ख़िताब जीता और वैश्विक रैंकिंग में उनकी बढ़त को और मज़बूत किया।

Key Points:-

(i) एन के शानदार 2025 सीज़न में अब 37-1 का रिकॉर्ड शामिल है, जिसमें लगातार छह बार फ़ाइनल में पहुँचना और जीत हासिल करना शामिल है। जापान ओपन में उनकी सफलता एक मामूली चोट से उबरने के कुछ ही हफ़्तों बाद आई, जिससे उनकी फिटनेस, एकाग्रता और अनुकूलन क्षमता का पता चलता है। आने वाले वर्षों में ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए वह दक्षिण कोरिया की सबसे मज़बूत उम्मीद बनी रहेंगी।

(ii) व्यक्तिगत उपलब्धियों के अलावा, जापान ओपन का यह संस्करण दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण रहा। चीन ने तीन खिताब जीते—पुरुष एकल, महिला युगल और मिश्रित युगल—जबकि दक्षिण कोरिया ने पुरुष युगल और महिला एकल सहित दो खिताब जीते।

(iii) 950,000 अमेरिकी डॉलर की कुल पुरस्कार राशि के साथ, जापान ओपन 2025 ने ओलंपिक योग्यता और विश्व रैंकिंग में सुधार के लिए बीडब्ल्यूएफ कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की।

2. युवा भारतीय गोताखोर पलक शर्मा सिंगापुर में 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने वाली सबसे कम उम्र की गोताखोरों में शामिल हैं।

इंदौर, मध्य प्रदेश की एक होनहार गोताखोर पलक शर्मा, 11 जुलाई से 3 अगस्त तक सिंगापुर में होने वाली विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। लगभग 16-17 वर्ष की आयु में, वह इस वैश्विक आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की गोताखोरों में से एक हैं।

• 28 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त को होने वाली तीन डाइविंग स्पर्धाओं के लिए चुनी गई पलक का विश्व चैंपियनशिप में लगातार दूसरा प्रदर्शन है, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुर्लभ भारतीय महिलाओं में से एक बन गई हैं। उनकी वापसी भारतीय तैराकी महासंघ द्वारा उनकी क्षमता पर निरंतर विश्वास को दर्शाती है।

• पलक की प्रशिक्षण यात्रा उल्लेखनीय है। विश्वामित्र पुरस्कार विजेता रमेश व्यास द्वारा प्रशिक्षित, वह प्रतिदिन लगभग आठ घंटे अभ्यास करती है, यहाँ तक कि स्कूल में बदलाव और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी - छत के डिज़ाइन से लेकर घर के सेटअप तक।

• उनकी लगन ने उन्हें 38वें राष्ट्रीय खेलों (अंडर-19) में तीन स्वर्ण और 2024 सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक दिलाया, साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और मध्य प्रदेश के एकलव्य पुरस्कार जैसे सम्मान भी दिलाए।

Key Points:-

(i) पलक शर्मा 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में तीन डाइविंग स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं: 1 मीटर स्प्रिंगबोर्ड, 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड और 10 मीटर प्लेटफ़ॉर्म, जिससे वह डाइविंग के विभिन्न विषयों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। उनकी योग्यता राष्ट्रीय स्तर पर उनके लगातार प्रदर्शन और भारतीय तैराकी महासंघ (SFI) द्वारा आयोजित ट्रायल्स पर आधारित है।

(ii) वर्ल्ड एक्वेटिक्स (पूर्व में FINA – फेडरेशन इंटरनेशनेल डी नैटेशन) द्वारा आयोजित विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025, 11 जुलाई से 27 जुलाई, 2025 तक सिंगापुर में आयोजित की जाएगी—जो देश का पहला मेज़बान होगा। इस संस्करण में छह जलीय खेल शामिल हैं और यह 2026 के युवा ओलंपिक और 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए क्वालीफायर के रूप में कार्य करता है।

(iii) पलक, जिन्होंने इससे पहले 2023 एशियाई आयु वर्ग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और पोडियम स्थान हासिल किया था, भोपाल स्थित मध्य प्रदेश राज्य एक्वेटिक अकादमी में कोच कमलेश नानक के अधीन प्रशिक्षण ले रही हैं। उनकी प्रगति भारत की खेलो इंडिया पहल की सफलता और जलीय खेलों में महिलाओं के लिए बढ़ते राज्य समर्थन को दर्शाती है।

3. आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की।

वेस्टइंडीज के गतिशील ऑलराउंडर आंद्रे ड्वेन रसेल ने आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह जुलाई 2025 में जमैका के किंग्स्टन में सबीना पार्क में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो T20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) मैचों के बाद संन्यास ले लेंगे।

• 37 वर्ष की उम्र में रसेल ने विस्फोटक प्रदर्शन और वैश्विक टी-20 प्रभुत्व से चिह्नित अपने करियर का समापन किया।

• रसेल ने 2010 में वेस्टइंडीज के लिए पदार्पण किया और खेल के तीनों प्रारूपों: टेस्ट क्रिकेट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ODI) और T20I में हिस्सा लिया। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में, उन्होंने एक टेस्ट मैच, 56 एकदिवसीय मैचों में 1,034 रन बनाए और 70 विकेट लिए, और 84 T20I मैचों में 1,078 रन बनाए और 61 विकेट लिए।

• रसेल को 2012 और 2016 में ICC (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) पुरुष T20 विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में जाना जाता है। जुलाई 2025 में उनके अंतिम T20I ने उनके जाने के लिए एक उत्सव का माहौल बना दिया - विशेष रूप से सबीना पार्क में टीम के साथियों और विरोधियों से गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करना।

Key Points:-

(i) अपने भावुक विदाई समारोह में रसेल ने 15 गेंदों पर 36 रन की अपनी विशिष्ट पारी खेली, जिसमें छह छक्के और दो चौके शामिल थे। वेस्टइंडीज की आठ विकेट से हार के बावजूद, मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रसेल मैदान से बाहर चले गए।

(ii) उन्होंने अपने करियर पर विचार करते हुए कहा, "शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि इसका क्या मतलब था। वेस्टइंडीज़ का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धियों में से एक रहा है," और उन्होंने कैरेबियाई क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने की इच्छा व्यक्त की।

(iii) आगे की बात करें तो, रसेल T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में से एक के रूप में एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ रहे हैं। आगे चलकर, कैरेबियाई टीम मैथ्यू फोर्ड, ज्वेल एंड्रयू और जेडिया ब्लेड्स जैसी नई प्रतिभाओं के साथ आगे बढ़ेगी, जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई T20 सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया गया था।

AWARDS

1. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर है।

जुलाई 2025 में, न्यूयॉर्क स्थित ट्रैवल + लीज़र पत्रिका ने इस्तांबुल हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे पसंदीदा

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया, जिसके बाद सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर रहा। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नौवें स्थान पर रहा, और लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक शीर्ष 10 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा बन गया।

• इस्तांबुल हवाई अड्डे ने ट्रैवल + लीजर 2025 पुरस्कारों में 98.57 के शानदार पाठक स्कोर के साथ अपनी नंबर-वन रैंकिंग बरकरार रखी, जो 2024 में 95.79 थी। इसकी आधुनिक डिजाइन, बढ़ती वैश्विक कनेक्टिविटी और बेहतर यात्री अनुभव ने इसे वैश्विक यात्रियों के लिए शीर्ष विकल्प बना दिया है।

• सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा 95.20 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो अपने प्रतिष्ठित इनडोर झरनों, लगभग 600,000 पौधों वाले हरे-भरे इनडोर उद्यानों, असाधारण खरीदारी के अनुभव और निर्बाध परिचालन के लिए जाना जाता है।

• शीर्ष पाँच में शामिल अन्य शीर्ष रेटेड हवाई अड्डों में दोहा का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (तीसरा), अबू धाबी का ज़ायेद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (चौथा) और दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (पाँचवाँ) शामिल हैं। हांगकांग, फ़िनलैंड और टोक्यो के हवाई अड्डे भी शीर्ष आठ में शामिल हैं।

Key Points:-

(i) मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA) 84.23 अंकों के साथ दक्षिण कोरिया के इंचियोन हवाई अड्डे से आगे निकलकर विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर रहा। यह शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है और इसे लगातार तीसरे वर्ष यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

(ii) अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के तहत मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) द्वारा प्रबंधित, CSMIA ने वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 55.12 मिलियन यात्रियों को संभाला और लगभग 1,000 दैनिक हवाई यातायात आंदोलनों के साथ 54 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और 67 घरेलू गंतव्यों के लिए सीधी कनेक्टिविटी बनाए रखी।

(iii) यह हवाई अड्डा हाल ही में भारत का पहला और विश्व का तीसरा ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जिसे एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) से लेवल 5 एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय उन्नयनों में एक नया एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, 68 इलेक्ट्रॉनिक गेट, सेल्फ-सर्विस चेक-इन टर्मिनल और डिजीयात्रा बायोमेट्रिक पासपोर्ट-मुक्त प्रणाली का विस्तार शामिल है।

IMPORTANT DAYS

1. भारत ने 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 मनाया, जो भारतीय प्रसारण कंपनी की 98वीं वर्षगांठ थी।

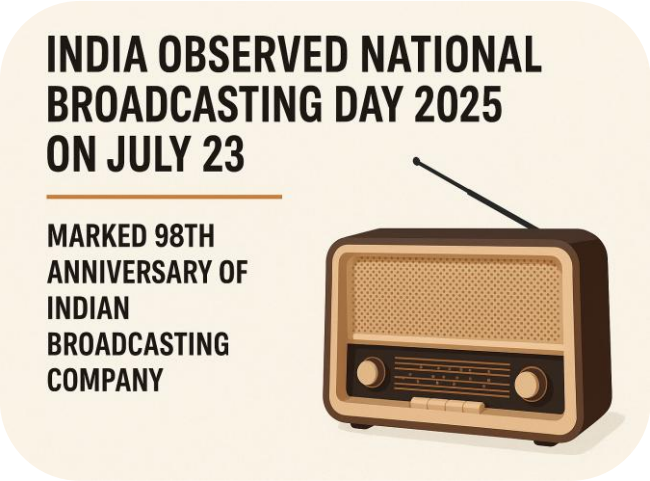

भारत ने 23 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया, जो 1927 में बॉम्बे (अब मुंबई) में भारतीय प्रसारण कंपनी (IBC) की स्थापना के साथ रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद दिलाता है। यह दिन जनसंचार के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में रेडियो की विरासत और डिजिटल युग में इसके विकास का सम्मान करता है।

• इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) एक निजी स्वामित्व वाला रेडियो स्टेशन था जिसने 23 जुलाई,

1927 को भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी।

• बाद में इसे सरकार ने अपने अधीन ले लिया और 8 जून, 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो (AIR) कर दिया गया। 2025 तक, इस घटना को 98 साल पूरे हो जाएंगे, जो भारत की सार्वजनिक संचार प्रणाली में रेडियो के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है।

• IBC से पहले, भारत में पहला रेडियो प्रसारण जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा किया गया था। इस प्रायोगिक प्रसारण ने संरचित प्रसारण के लिए आधार तैयार किया और व्यापक दर्शकों तक समाचार, सूचना और सांस्कृतिक सामग्री पहुंचाने में रेडियो की क्षमता पर प्रकाश डाला।

Key Points:-

(i) ऑल इंडिया रेडियो (AIR), आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी, भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक बन गया, जिसने राष्ट्रीय एकीकरण, ग्रामीण पहुंच और क्षेत्रीय भाषाओं में जन जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से टीवी युग से पहले।

(ii) आकाशवाणी प्रसार भारती (PB) के अधीन कार्य करता है, जो प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित भारत की स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारण एजेंसी है। PB राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारक, दूरदर्शन का भी संचालन करता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती पूरे देश में निष्पक्ष समाचार और शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करने के अपने मिशन को जारी रखे हुए है।

(iii) डिजिटल युग में, हालाँकि नए प्लेटफ़ॉर्म उभरे हैं, रेडियो अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है, खासकर दूरदराज के इलाकों में। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 पर, राष्ट्र रेडियो की अनुकूलनशीलता और आपदा प्रतिक्रिया, शिक्षा और समुदायों को जोड़ने में इसकी भूमिका को स्वीकार करता है, इस प्रकार 21वीं सदी में इसकी प्रासंगिकता की पुष्टि करता है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. BITS पिलानी स्थित स्टार्ट-अप एपोलियन डायनेमिक्स ने भारतीय सेना को स्वदेशी ड्रोन वितरित किए।

जुलाई 2025 में, BITS (बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस), पिलानी-हैदराबाद कैंपस से जुड़े डिफेंस-टेक स्टार्टअप अपॉलियन डायनेमिक्स ने स्वदेशी रूप से विकसित UAVs (अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स) भारतीय सेना को सौंपे। यह भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और ड्रोन युद्ध प्रणाली में एक बड़ी उपलब्धि है।

• जयंत खत्री और सौन्य चौधुरी द्वारा स्थापित, अपॉलियन डायनेमिक्स की शुरुआत हॉस्टल प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। इस स्टार्टअप ने पूरी तरह भारत में विकसित ड्रोन बनाए हैं, जो भारतीय सेना की जरूरतों और जटिल भू-भाग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं।

• भारतीय सेना ने इन ड्रोन को चार प्रमुख सैन्य ठिकानों पर तैनात किया है—जम्मू (जम्मू और कश्मीर), चंडीमंदिर (हरियाणा), पनागढ़ (पश्चिम बंगाल) और अरुणाचल प्रदेश। ये सभी स्थल रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और सीमाई तथा आतंक विरोधी अभियानों से जुड़े क्षेत्र हैं।

Key Points:-

(i) ये रडार से बच निकलने वाले 'कामिकाज़े' ड्रोन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से उड़ सकते हैं और 1 किलोग्राम तक का सटीक पेलोड ले जा सकते हैं। इनकी हाई-स्पीड और स्टेल्थ तकनीक सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में त्वरित हमलों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

(ii) सेना के जवानों को इन ड्रोन को संचालित करने हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, जिससे बिना पूर्व तकनीकी जानकारी वाले सैनिक भी इन्हें प्रभावी ढंग से चला सकते हैं। यह प्रशिक्षण फील्ड में तुरंत उपयोग के लिए तैयार करता है।

(iii) अपॉलियन डायनेमिक्स की टीम में बीआईटीएस के छह द्वितीय वर्ष के छात्र भी शामिल हैं, जो अगली पीढ़ी की VTOL (वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग) और फिक्स्ड विंग ड्रोन तकनीक पर कार्य कर रहे हैं। ये नई तकनीकें भविष्य की सैन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित की जा रही हैं।

ENVIRONMENT

1. उत्तराखंड ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय हिमालयी प्रजातियों को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत का पहला व्यवस्थित पौध संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया।

जुलाई 2025 में, उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान प्रभाग ने भारत का पहला व्यवस्थित पादप संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य पश्चिमी हिमालय में 14 गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप प्रजातियों को उनके मूल निवास स्थानों में पुनः स्थापित करना है। मानसून के मौसम के साथ शुरू की गई यह पहल, उपयुक्त विकास परिस्थितियों को सुनिश्चित करती है और भारत के जैव विविधता पुनर्स्थापन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- **संरक्षण कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है, तथा इसे आईयूसीएन (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) रेड लिस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है।**

- **यह भारत की पहली औपचारिक पौध पुनरुत्पादन पहल है, जिसका उद्देश्य उन प्रजातियों को पुनर्जीवित करना है जो पारिस्थितिक दबावों के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं।**

- **चयनित 14 पौधों की प्रजातियों में हिमालयन जेंटियन, व्हाइट हिमालयन लिली, रेड क्रेन ऑर्किड, गोल्डन हिमालयन स्पाइक, ट्रून चीज़ वुड, कुमाऊँ फैन पाम, इंडियन स्पाइकनार्ड, पटवा और हिमालयन अर्नेबिया आदि शामिल हैं। इन पौधों का औषधीय, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है और ये अत्यधिक कटाई, आवास के नुकसान और जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।**

Key Points:-

(i) प्रत्येक पौधे की प्रजाति का प्रसार उच्च-ऊंचाई वाली नर्सरियों में प्रजाति-विशिष्ट तकनीकों का उपयोग करके किया जा रहा है। स्वस्थ पौधों को जंगल में पुनः स्थापित करने के लिए बीज अंकुरण, कंद रोपण, प्रकंद विभाजन और तने की कटिंग जैसी विधियों का उपयोग किया जा रहा है।

(ii) पुनर्रोपण प्रक्रिया में हिमालय के पारिस्थितिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें अल्पाइन घास के मैदान, पर्णपाती वन और तराई क्षेत्र

शामिल हैं। प्रत्येक रोपण स्थल पर नज़र रखने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) मैपिंग का उपयोग किया जा रहा है, जिससे रोपण के बाद निगरानी और दीर्घकालिक संरक्षण सफलता सुनिश्चित हो सके।

(iii) इस पहल का उद्देश्य न केवल देशी जैव विविधता को बहाल करना है, बल्कि भारत के हिमालयी और वन पारिस्थितिकी तंत्र में भविष्य के जलवायु-लचीले संरक्षण मॉडल के लिए एक मिसाल भी स्थापित करना है।

Static GK

SEBI	अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे	मुख्यालय: मुंबई
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
World Bank	CFO : अंशुला कांत	मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
Travel + Leisure Co	CEO : माइकल डी. ब्राउन	मुख्यालय : फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
Uttarakhand	मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी	राज्यपाल: गुरमित सिंह
Badminton World Federation (BWF)	राष्ट्रपति : खुनयिंग पटामा लीस्वाडत्रकुल	मुख्यालय : कुआलालंपुर, मलेशिया
China	राष्ट्रपति: शी जिनपिंग	आधिकारिक भाषाएँ: मंदारिन, पुतोंगहुआ
United Kingdom	राजधानी: लंदन	प्रधानमंत्री: कीर स्टारमर
MoHFW	मंत्री: श्री जगत प्रकाश नड्डा	मुख्यालय: नई दिल्ली
PhonePe	CEO : समीर निगम	मुख्यालय: सलारपुरिया सॉफ्टज़ोन, बेंगलुरु, कर्नाटक
Prasar Bharati (PB)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : गौरव द्विवेदी	मुख्यालय: नई दिल्ली